Sri Lankan Tamil refugees from India to Sri Lanka and the process of resettlement of displaced persons in Sri Lanka is continuing.

As envisaged under the Agreement, India has extended military assistance to Sri Lanka to implement the proposals contained in the Agreement, to ensure the physical security and safety of all communities in the Northern and Eastern Provinces and for disarming the militants.

The clauses not yet implemented include: the disarming of all Tamil militants; holding of Provincial Council elections to the North-Eastern Province; the merger of the Nothern and Eastern Province which will come into effect from the date of elections to the combined provincial Council.

As regards the provisions of the Annexure and the Exchange of letters, which form a part of the Agreement, the Government of India is in continuous touch with the Government of Sri Lanka.

(d) Both Governments are in constant touch to ensure the full implementation of the Agreement. Government has also been in touch with various Tamil groups to try to ensure their participation in the implementation of the Agreement.

परमाणु संयंत्रों द्वारा बिजली का उत्पादन

4435. **श्री राम जेठमलानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस सदी के अन्त तक परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया था ।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इस प्रयोजनार्थ कोई समयबद्ध योजना तैयार की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किसी बाहरी देश से कोई करार करने का विचार रखती है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग ने यह लक्ष्य रखा कि इस शताब्दी के अन्त तक परमाणु बिजलीघरों की स्थापित क्षमता कुल मिलाकर 10,000 मेगावाट कर दी जाय ।

(ग) तथा (घ) इस समय 6 यूनिट काम कर रहे हैं जिनकी कुल क्षमता 1230 मेगावाट है । आठ यूनिटों का निर्माण-कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट होगी । इनमें से दो दो यूनिट उत्तर प्रदेश में नरोरा नामक स्थान पर, गुजरात में ककरापार नामक स्थान पर, कर्नाटक कैगा नामक स्थान पर और राजस्थान में रावत-भाटा नामक स्थान पर लगाये जा रहे हैं । इन परियोजनाओं के पूरा होने पर परमाणु बिजलीघरों की स्थापित क्षमता बढ़कर 3110 मेगावाट हो जायेगी । 235 मेगावाट क्षमता वाले 4 और यूनिटों तथा 500 मेगावाट वाले 6 यूनिटों का निर्माण-कार्य सातवीं योजना की अवधि में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है । इस शताब्दी के अन्त तक परमाणु बिजलीघरों की स्थापित क्षमता को बढ़ाकर लगभग 10,000 मेगावाट कर देने के उद्देश्य से 500 मेगावाट क्षमता वाले 6 और यूनिट का निर्माण-कार्य आठवीं योजना की अवधि में शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है । इस लक्ष्य को रा करने में किसी अन्य देश के साथ करार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । सोवियत संघ के सहयोग से 1000 मेगावाट क्षमता वाले बाबित हल्का पानी किस्म के दो रिएक्टर

लगाना, जिसके बारे में एक करार विचाराधीन है, उस कार्यक्रम के अतिरिक्त है जिस के अन्तर्गत सन् 2000 तक 10000 मेगावाट क्षमता के रिएक्टर लगाये जाने हैं।

बांगलादेश में अल्पसंख्यकों के संबंध में श्रीमती शेख हसीना वाजेद का कथित वक्तव्य

4436. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री राम अवधेश सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बांगलादेश की अवामी लीग पार्टी की नेता श्रीमती शेख हसीना वाजेद द्वारा कलकत्ता विमान पत्तन पर दिये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि बांगलादेश में अब अल्पसंख्यक अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं। तथापि, बांगलादेश की सरकार ने ढाका स्थित हमारे हाई कमीशन को यह आश्वासन दिया है कि वहां के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जायगी।

सिंचाई क्षमता का उपयोग

4437. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है ;

(ख) तो क्या यह भी सच है कि इस क्षमता के उपयोग को बढ़ाने के लिये कमांडर एरिया डिवलपमेंट कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो पिछले 3 वर्षों के दौरान देश की सिंचाई क्षमता कितनी रही; और इस क्षमता के उपयोग की स्थिति क्या रही ; और

(घ) सरकार ने इस क्षमता के अधिकतम उपयोग का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) छठी योजना अवधि के अन्त तक, 67.53 मिलियन हेक्टेयर की सृजित सिंचाई क्षमता की तुलना में 60.58 मिलियन हैक्टर की क्षमता का उपयोग किया जा रहा था।

(ख) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अन्यों के साथ-साथ सिंचाई क्षमता के उपयोग में सुधार करना है।

(ग) सिंचाई क्षमता (मिलियन हेक्टेयर में)

छठी योजना (1984–85) तक सृजित	67.53	छठी योजना–1984–85 तक उपयोग की गयी	60.58
1985–86 (उपलब्धि)	2.09	1985–86 उपलब्धि	1.55
1986–87 (प्रत्याशित उपलब्धि)	2.32	1986–87 प्रत्याशित उपलब्धि	2.04
1987–88 (लक्ष्य)	2.38	1987–88 (लक्ष्य)	2.05